



INNOVATIVE INSTITUTE OF LAW

Approved by Bar Council of India (BCI), Delhi & Affiliated To CCS University, Meerut, U. P.

Self Study Report

NAAC 1st Cycle

Matrix No. 2.1.1

Affiliation Orders of last five years



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

Ref.No.:- Affi./1711

Dated: 16.8.2024

TO WHOM IT MAY CONCERN

This to certify that Innovative Institute of Law, Plot No. 06, Knowledge Park-2, Greater Noida, Gautam Budh Nagar is affiliated to the Chaudhary Charan Singh University, Meerut and the following Courses/Subjects are taught in the said college as per approval.

Sl. No.	Name of the Course	Affiliation
01-	LL.B (Three Years)	Permanent Affiliation
02-	B.A.LLB (Five Years)	Permanent Affiliation

↓
↓
↓
PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308

↓
↓
↓
16.8.2024
Registrar
Registrar
Ch Charan Singh University
Meerut

PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/३४७६

दिनांक : २ फरवरी, २००९

२००९

सचिव,

इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ,
ग्रेटर नोएडा

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-२, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या सम्ब०-१७९/सत्तर-२-२००८-२ (२८४)/२००८, दिनांक ३०.१२.२००८ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, २००७) की धारा-३७(२) के परन्तुक के अधीन इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ग्रेटर नोएडा को एल-एल०बी० (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२००८ से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

१. महाविद्यालय द्वारा बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया की मान्यता प्राप्त करने के पश्चात ही छात्रों को प्रवेश प्रदान किया जायेगा। तथा बार कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जायेगा।
२. संस्था शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६(९२)/२००२ दिनांक २ जुलाई २००३ एवं शासनादेश संख्या-४१०८/सत्तर-२-२००७-२(४९४)/२००७, दिनांक १७ अक्टूबर, २००७ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
३. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय शासन एवं बार कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ग्रेटर नोएडा का एल-एल०बी० (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२००८ से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

१. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
२. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
३. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
४. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
५. सचिव, बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, २१, राजज एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-२ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

PRINCIPAL
Innovative Institute of Law

कुलसचिव

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, गेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/2786
दिनांक : 3/9/11

सचिव
इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ,
ग्रेटर नोएडा

गहोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-1610/सत्तर-2-2011-2(317)/2010, दिनांक 10.08.2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ग्रेटर नोएडा को बी0ए0-एल-एल0बी0 (पाँच वर्षीय) पाठ्यक्रम/विषय में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2010 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्रवाही नियमानुसार की जायेगी।

शासन एवं बार कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ग्रेटर नोएडा को बी0ए0-एल-एल0बी0 (पाँच वर्षीय) पाठ्यक्रम/विषय में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2010 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय/बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
3. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. सचिव, बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, 21, राउज एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम वेबसाइट पर डालने का कष्ट करें।

PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता / ४२१६
दिनांक : २ फरवरी, २००९
२१११

सचिव,
इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ,
ग्रेटर नोएडा

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग २, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या सम्ब०-१७९/सत्तर-२-२००८-२ (२८४)/२००८, दिनांक ३०.१२.२००८ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, २००७) की धारा-३७(२) के परन्तुक के अधीन इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ग्रेटर नोएडा को एल-एल०बी० (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२००८ से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

१. महाविद्यालय द्वारा बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया की मान्यता प्राप्त करने के पश्चात ही छात्रों को प्रवेश प्रदान किया जायेगा तथा बार कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जायेगा।
 २. संस्था शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६(९२)/२००२ दिनांक २ जुलाई २००३ एवं शासनादेश संख्या-४१०८/सत्तर-२-२००७-२(४९४)/२००७, दिनांक १७ अक्टूबर, २००७ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
 ३. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- माननीय शासन एवं बार कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ग्रेटर नोएडा को एल-एल०बी० (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२००८ से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

PRINCIPAL

Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308.

भवदीय,

42

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

१. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
२. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
३. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
४. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
५. सचिव, बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, २१, राउज एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-२ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कुलसचिव

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/2786
दिनांक 3/10/11

सचिव
इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ,
ग्रेटर नोएडा

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-1610/सत्तर-2-2011-2(317)/2010, दिनांक 10.08.2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ग्रेटर नोएडा को बी0ए0-एल-एल0बी0 (पाँच वर्षीय) पाठ्यक्रम/विषय में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2010 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

शासन एवं बार कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ग्रेटर नोएडा को बी0ए0-एल-एल0बी0 (पाँच वर्षीय) पाठ्यक्रम/विषय में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2010 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय/बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
3. प्रभारी, कमेंटी, सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. सचिव, बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, 21, राउज एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम दैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।

PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/192
दिनांक : 29.12.2005

सचिव,
इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ,
प्लॉट नं०-6, नोलेज पार्क-II,
ग्रेटर नोएडा

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स. 1665/जी.एस. दिनांक 05.08.2005 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके संस्थान को कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1978 की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ग्रेटर नोएडा को स्नातक स्तर पर विधि संकाय में एल-एल-बी० (पाँच एवं तीन वर्षीय) पाठ्यक्रमों में क्रमशः (80 एवं 160) सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2005 से आगामी क्रमशः पाँच एवं तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र 'बी' में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्रबन्ध तंत्र का चुनाव/अनुमोदन विश्वविद्यालय से करा लिया जायेगा।
3. महाविद्यालय द्वारा लॉ कालिज की पृथक भूमि के अभिलेख प्रस्तुत करते हुए भूमि संस्था के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा लिए जाने की सूचना शासन के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।
4. महाविद्यालय द्वारा प्रबन्ध तंत्र का अनुमोदन करा लिया जायेगा एवं मानकानुसार शिक्षकों की नियुक्ति कर उन पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
5. संस्था बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया की अनुमति के पश्चात् ही विद्यार्थियों का प्रवेश लेगी एवं कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगी कि सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रही हैं।
6. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 03 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।
7. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं बार काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1978 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार एल-एल०बी० (पाँच एवं तीन वर्षीय) पाठ्यक्रमों में क्रमशः (80 एवं 160) सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उक्त निर्धारित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2005 से आगामी क्रमशः पाँच एवं तीन वर्ष हेतु उपरोक्त शर्तों तथा बार कौंसिल ऑफ इण्डिया की शर्तों के अधीन सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308

कुलसचिव
Anil Kumar

प्रतिलिपि:-

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
2. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय को आगामी कार्यपरिषद की बैठक के सूचनार्थ।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

Grams : ALINDIABAR, New Delhi
Fax : Off. (91) 011-23231767
E-mail : bci.india@hub.nic.in
Website : www.barcouncilofindia.nic.in



Office : 23231647
Phones : Secy's 23231648
Resi. : 22786209
22732923

बार कौंसिल ऑफ इन्डिया BAR COUNCIL OF INDIA

21, राउज ऐवन्यू इन्स्टीटूशनल एरिया
नई दिल्ली - 110 002
21, Rouse Avenue Institutional Area
New Delhi - 110 002

BCI: D: 18/11 2005 (LE: Mtg.) (136- UP)

17.12.2005

Regd. A. D.

The Registrar
Ch. Charan Singh University
Meerut,
UP

**SUB:- TEMPORARY APPROVAL OF AFFILIATION OF
Innovative Institute of Law, Greater Noida , UP**

Sir,

The Report of Inspection of the above law college was placed before the Bar Council of India at its meeting held on 11th and 12th December, 2005. After consideration Council took the following decision:-

"The Bar Council of India considered the inspection report of **Innovative Institute of Law, Greater Noida, UP** submitted by the inspection team of the Bar Council of India. After consideration Council is of the view that the above mentioned college may be granted temporary approval of affiliation to the above said college to run 3 year as well as 5 year law course with intake of two sections of 80 students in each section in three year law course and one section of 80 students in five year law course for the academic year 2005-2006 and 2006-2007 with the following conditions:-

1. A sum of Rs. 1 lac should be spent immediately for books.
2. UGC scale be paid to teachers through cheque
3. In library proper almirahs should be constructed within a period of one month.

Further management of the College is required to file an affidavit in the Bar Council of India within a period of two months to the effect that compliance of the conditions mentioned in the inspection report have been carried out."

PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308

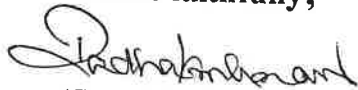
The College shall also comply with the following Rule 23 in Section A and Rule 16 in Section B in Part IV of the Bar Council of India Rules respectively:

“Whenever approval of affiliation is granted to the law college it shall be necessary for the college to deposit in cash Rs.1,00,000/- (one lakh) in the shape of guarantee to fulfil all the norms of the Bar Council of India. The same shall be liable to be forfeited if the norms are not complied with and the same shall carry no interest.”

The approval of affiliation now granted by the Bar Council of India is subject to the payment of guarantee amount as mentioned in the above rule.

You are also required to apply to the Bar Council of India for further extension of approval of affiliation six months in advance before expiry of the period of approval of affiliation granted by the Bar Council of India.

Yours faithfully,


(S. Radhakrishnan)
Secretary

CC:-

1. ✓ THE PRINCIPAL
INNOVATIVE INSTITUTE OF LAW
PLOT NO. 6 KNOWLEDGE PART-2
GREATER NOIDA, UP
2. The Secretary,
Bar Council of Uttar Pradesh
19, Maharishi Dayanand Marg,
Allahabad-211 001, UP

Encl : copy of inspection report

P.S. The amount may be remitted by way of crossed Demand Draft drawn in favour of the 'Legal Education Fund Account of the Bar Council of India' on any Nationalised Bank payable at Delhi.

KLS/RKS

PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक :- सम्बद्धता/1771
दिनांक :- 29.08.2005
2-9

सेवा में,
सचिव,
बार कौंसिल ऑफ इण्डिया,
नई दिल्ली।

विषय :- इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ग्रेटर नोएडा को एल-एल0बी0 (तीन एवं पाँच वर्षीय) पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2005-06 से अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ग्रेटर नोएडा को एल-एल0बी0 (तीन एवं पाँच वर्षीय) में माननीय कुलाधिपति महोदय के पत्र संख्या ई0स0/1665/जी0एस0 दिनांक 05.08.2005 के द्वारा दिनांक 01.07.2005 से आगामी तीन एवं पाँच वर्ष हेतु सम्बद्धता प्रदान कर दी गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ग्रेटर नोएडा को एल-एल0बी0 (तीन एवं पाँच वर्षीय) में बार कौंसिल ऑफ इण्डिया की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

भवदीय

01
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

01. सचिव, इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ग्रेटर नोएडा।

कुलसचिव

PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308



INNOVATIVE INSTITUTE OF LAW

Approved by Bar Council of India (BCI), Delhi & Affiliated To CCS University, Meerut, U. P.

Self Study Report

NAAC 1st Cycle

Matrix No. 2.1.1

**Affiliation Orders of last five years from
Statutory Body (Bar Council of India)**

E-mail : bcinfo21@gmail.com
info@barcouncilofindia.org
Website : www.barcouncilofindia.org



Tel : (01) 011-4822 5000
Fax : (01) 011-4822 5011

भारतीय विधिज्ञ परिषद् BAR COUNCIL OF INDIA

(Statutory Body Constituted under the Advocates Act, 1961)

BCI: 21, Rouse Avenue Institutional Area, Near Bal Bhawan, New Delhi - 110002
21) /2024 (LE/App/Affin) 31.07.2024

1.	The Registrar, Chaudhary Charan Singh University, Meerut, Uttar Pradesh
2.	The Principal, Innovative Institute of Law, Plot No. 6, Knowledge Park - 2, Greater Noida, Uttar Pradesh - 201308

Sub: Extension of provisional approval of affiliation to Innovative Institute of Law, Greater Noida, Uttar Pradesh for imparting three year LL.B course with intake of three sections of 60 students in each sections, five year BA LL.B course with intake of two sections of 60 students in each sections, and five year B.Com LL.B course with intake of one section of 60 students for a period of one year i.e. for the academic year 2024-2025.

Sir/Ma'am,

This is with reference to above mentioned subject regarding extension of provisional approval of affiliation to Innovative Institute of Law, Greater Noida, Uttar Pradesh which has already applied for extension of approval of affiliation for the academic year 2024-2025.

This is to bring to your kind knowledge that the following resolution was passed on 5th May, 2024 by the General Council of the Bar Council of India with respect to grant of provisional approval of affiliation, to existing Centers of Legal Education/Colleges, whose approval cum regular inspection fee has been deposited, application of extension of approval of affiliation is pending, but no inspection could be done or the inspection has been done, but inspection report could not be placed before the Legal Education Committee or the Standing Committee for the academic year 2024-2025.

*RESOLVED that with respect to existing Centers of Legal Education/Colleges, whose inspection fee has been deposited, application for extension of approval of affiliation is pending, no inspection could be done or the inspection has been done, but inspection report could not be placed before the Legal Education Committee or the Standing Committee for its consideration, such Centers of Legal Education/Colleges may continue to admit students only for the academic year 2024-2025. This will apply only in case where affiliation has been granted by the University. Such provisional approval shall be subject to any decision taken after the inspection of the CLE is done by the Bar Council of India subsequently.

Typed by: M.J.
For & On Checked: M.J.

✓
PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No-6 Knowledge Park-2
Greater Noida - 201308

AN AFFIDAVIT THAT THE CENTRE OF LEGAL EDUCATION IS COMPLYING WITH THE BELOW STIPULATED NORMS, RULES, REGULATIONS AND MANDATORY GUIDELINES OF BAR COUNCIL OF INDIA AS WELL AS WITH ALL THE ENUMERATIONS STIPULATED IN THE ATTACHED CIRCULARS(WITH THIS LETTER) BEARING NOS. BCI: D: 465/2024 DATED 24.01.2024(ANNEXURE-B), BCI: D: 468/2024/CIR-006/2024(LE) DATED 20.05.2024(ANNEXURE-C), BCI: D: 469/2024(LE/CIR.007) DATED 21.05.2024 (ANNEXURE-D)AND BCI:D:525/2024 (LE CIRCULAR NO. 008/2024) DATED 30.05.2024(ANNEXURE-E) AND SHOW CAUSE NOTICES AND COMPLIANCE LETTER REFERRED TO IN ANNEXURE-A, ATTACHED TO THIS LETTER MUST BE SUBMITTED TO THE BAR COUNCIL OF INDIA WITHIN 15 DAYS OF THE RECEIPT OF THIS LETTER FAILING WHICH, THEIR APPLICATION FOR FURTHER EXTENSION OF APPROVAL OF AFFILIATION SHALL NOT BE CONSIDERED AND IF APPROVAL, IS GRANTED FOR THE ACADEMIC SESSION 2024-2025, THE SAME MAY BE WITHDRAWN TOO.

The provisional approval of affiliation shall be conditional and is subject to compliance as per circular dated 05.02.2020 bearing No.BCI:D:158 (LE:Circulation No.01/2020), issued to all Centers of Legal education, as per the extended time of such compliance, whereby every Centre of Legal Education/college is required to submit a certified authenticated bank statement bearing bank stamp, date and signature, mandatorily with respect to the salary/ies being disbursed to all the teachers/faculties every three months with effect from March, 2022 on a regular basis, unless specifically sought at other intervals, and also furnish list of teachers with qualifications as per BCI and UGC Rules, and further furnish proof/receipts of fulfillment of minimum library requirements, as enumerated under Schedule-III, Rule-15, Minimum Library requirements of Legal Education Rules-which is the sine qua non of a Centre of Legal Education. Certain show cause notices and compliance letters had also been issued specifically to certain Centers of Legal Education/Colleges, with conditions mentioned therein, which have to be complied too as per the time stipulations therein, and if they have not been complied with they must be complied with immediately.

The last date for compliance of the above referred circular has expired on 31st August, 2022. It was extended from time to time due to the pandemic. As a last opportunity, ensure to comply with the same, otherwise the provisional approval of affiliation being issued herewith may be withdrawn.

➤ You may kindly bear in mind that the Bar Council of India is the sole and supreme sanctioning authority for seats and it does not allow any supernumerary quota of seats for law degree courses, over and above the sanctioned strength of seats and whatever reservation of seats is to be done by the University under whichever quota as a rule has to be done within sanctioned strength of seats. The only supernumerary quota, as of now permitted by the Bar Council of India, is 10 percent seats in EWS quota over and above the sanctioned strength of seats allotted/approved by BCI and that too, is subject to adequate infrastructure and qualified faculty to accommodate the supernumerary seats. The same is required to be adhered to. If there is any default on such part and the same is discovered subsequently, action shall ensue.

Typed by: M.J
Fee & QA Checked: M.J

PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
6 Knowledge Park-2
201308

- The CLE is advised to declare the same voluntarily for consideration of the same in a manner which will not be detrimental to interests of the students admitted, if any, over and above the sanctioned seats as a one time opportunity. The same shall not be construed to be applied prospectively.
- It is pertinent to point that no University in India can offer a 4 year LL.B or integrated LL.B, followed by a 1 year LL.M in tie up with a foreign University under the present BCI regulations. Such a Law degree, nor the post qualification after it, is recognised by Bar Council of India. The BCI only recognizes the pattern of a 12th class +3 (graduation in any stream+3 (year Law degree) and/or a 12 + 5 year integrated law degree.
- While exchange programs of teachers and students have been undertaken by Centres of Legal Education including, Law Universities in India, Dual Degrees or joint Degrees with Foreign Universities have not been permitted or recognized by BCI. It is essential to emphasize that any foreign collaboration involving legal education institutions, must strictly adhere to the regulatory framework established by the Bar Council of India. It cannot compromise on the quality of legal education mandated by the BCI. It's worth noting that unless a degree is recognized by the BCI in India, it holds no validity within the country. Therefore, a degree obtained from an Indian University, being recognized solely in a foreign jurisdiction, without recognition in India, would be of no consequence to the university or its students.
- Recognition and approval of law degrees are exclusively within the purview of the Bar Council of India. Consequently, if, upon thorough evaluation it is determined Law degrees are being issued by Universities against the rules and norms of Bar Council of India, recognition of such degree/s shall be withdrawn and such degree holders shall not be entitled to be enrolled in any State Bar Council in India.
- BCI and its Legal Education Committee have time and again reiterated, stated and clarified, that it does not recognise LL.B and/or LL.M or any Law degree course through online mode, correspondence, open and/or distance learning mode.
- It has further come to the attention of the Bar Council of India and its Legal Education Committee that certain institutions are offering Master of Arts (MA) programs with a Law subject, in open and distance learning mode, or online mode which attempts to mimic the structure and content of a Master of Laws (LL.M.) program. Upon careful examination, it has been observed that such an endeavour is beyond the scope and intent of a Master of Arts Degree and is deemed impermissible. It is hereby clarified that such MA degrees will not be recognized by the BCI as equivalent to a Master of Laws (LL.M.) degree and for the purpose of teaching of LL.B. Course.

Typed by: M.J
 Fee & GA Checked: M.J

PRINCIPAL
 Innovative Institute of Law
 Plot No -6 Knowledge Park -2
 Greater Noida-201308

➤ It is crucial to clarify that the designation "MA" signifies "Master of Arts," whereas "LL.M." represents "Legume Magister," a Latin term denoting a "Master of Laws" Degree. The distinction between these two titles is significant, as an LL.M. degree is specifically tailored for graduates of law programs, whereas an MA degree encompasses a broader range of academic disciplines and is separate and distinguished from Master of Laws Degree. It is a deliberate attempt to bypass LL.M. in such a manner.

➤ The BCI emphasizes that an MA degree with a Law subject does not confer the same benefits or privileges as an LL.M. degree. Individuals holding an MA degree in Law will not be entitled to the benefits typically associated with possessing an LL.M. degree, nor will they be eligible to teach in LL.B degree programs. Pursuit of legal education at the postgraduate level, in the form of an LL.M. degree, is restricted to individuals who have completed their undergraduate legal studies while it is clarified that any specialized branch of law offered at the master's level, without the LL.B./BA.LL.B qualification as the requisite entry-level credential, shall not be recognised as equivalent to an LL.M. degree.

➤ It is imperative for all stakeholders in the legal education sector to understand that the distinction between an MA degree and an LL.M. degree is significant. An MA degree with a Law subject does not fulfil the requirements for recognition by the BCI as a qualification equivalent to an LL.M. degree.

➤ This serves to clarify the position of the BCI on the recognition of MA degrees with a Law subject and to prevent any misconceptions regarding their equivalence to LL.M. degrees.

➤ The BCI and its Legal Education Committee has further also observed that running an MA (with Law subject) by any such mode is an attempt to mimic an LL.M, which is also not permitted by such mode.

➤ It has also been brought to the notice of Bar Council of India that some entities claiming to be Centre of Legal Education are offering courses through distance education/correspondence mode, under the nomenclature of the degree of LL.M. or LL.M. professional, where anyone even without LL.B. can get an LL.M. degree, and, the same persons are also getting registered for Ph.D., appearing for UGC NET etc. thereby diluting quality of legal education.

➤ This is an illegal practice and Bar Council of India shall not hesitate in taking stringent action against such centres.

➤ As per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 29.08.2019 passed in Writ Petition (Civil) No.1510 of 2018, titled as Vinit Garg Vs. University Grants Commission and as per the earlier order of Hon'ble Supreme Court of India dated 03.11.2017 passed in Civil Appeal Nos.17869-17870, arising out of SLP No. 19807-19808/2012 in the case of Odisha Lift Irrigation Corp Ltd. Vs Ravi Shankar Patro&Ors., the Hon'ble Supreme Court has held that an University has to obtain permission from the concerned regulatory body for initiating/starting, opening and conducting any distance learning course/s.

- **As per UGC Regulations 4(A)(iv), (Open and Distance Learning Programmes & Online Programmes) Regulations, 2020, the Higher Educational Institution must have the approval or recommendations of the statutory or regulatory authority, in this case, the Bar Council of India (BCI), for offering law programs in Open and Distance Learning mode or Online mode.**
- **Explanation: Programmes as mentioned at clause (iv) shall be considered only when these are recommended by the respective statutory or regulatory authority or regulatory council to offer in Open and Distance Learning mode or Online mode, as applicable....."**
- **Furthermore, the Distance Education Bureau under UGC explicitly prohibits courses in engineering, law, medicine, dental, pharmacy, nursing, architecture, physiotherapy, applied arts, and other such programs from being offered through online mode without approval from the respective statutory or regulatory bodies.**
- **Some Universities, including some reputed Universities are running such programs in flagrant violation of clear directives and guidelines as stipulated above and without even having made a request or application to BCI in this regard. It is categorically made clear, such programs have no recognition and/or approval from BCI.**
- **CLE's must ensure to comply with these directives, failing which necessary action will ensue.**

An affidavit/undertaking to comply with the conditions mentioned above shall be required to be submitted by way of duly notarized affidavit within 15 days of receipt of this letter by way of hardcopy and also by way of scanned copy at compliances@institute2@gmail.com with heading- COMPLIANCE TO PROVISIONAL APPROVAL-REQUIREMENTS.

It is made clear that if any Centre of Legal Education, does not comply to above then their application for further extension of approval shall not be considered and, if, approval is granted for the academic session 2024-2025, it may be withdrawn.

Since your University has given affiliation for the academic year 2024-2025, You are hereby requested to allow Innovative Institute of Law, Greater Noida, Uttar Pradesh to admit students in imparting three year LL.B course with intake of three sections of 60 students in each sections, five year BA LL.B course with intake of two sections of 60 students in each sections, and five year B.Com LL.B course with intake of one section of 60 students for a period of one year i.e. for the academic year 2024-2025.

Please be aware that compliance with all conditions and the Rules of Legal Education is mandatory. Any discovered shortcomings or deficiencies, including those detected from portal registrations and forms, may lead to the withdrawal of approval granted to the CLE. Such deficiencies will also render the CLE ineligible to admit students in the next academic session

Additionally, the CLE may receive further compliance directives and may be subject to both surprise and scheduled inspections. To maintain your approval and affiliation, ensure full adherence to all Rules and Regulations of Legal Education

- Universities who have not yet completed one time online registration on the basis of the link/s sent on their official email id's are required to fill the registration form, & upload registered documents and photographs within a period of 21 days, failing which appropriate action will ensue.

The compliances and pending fee/ any other fee which may be payable in future may be kindly ensured to be complied with as and when intimated in the future.

Note: - That the Centre of Legal Education has not paid the guarantee amount of Rs Ten Lacs and undertake to pay the same in two installments within six months. The next extension will be issued subject to clearance of guarantee amount.

- Note - Kindly ensure to submit English translation of all documents being furnished by you in Hindi or in any other regional language to BCI.

- Note - Your University is requested to kindly verify the authenticity of the attached affiliation order submitted by the Centre of Legal Education and revert back to the Bar Council of India through e-mail as soon as possible.


- Note- In accordance with the Council resolution passed on February 20, 2022, the refundable guarantee amount per course, is set at Rs. 5 lakh. Additionally, (C.L.E.'s) who had previously deposited a guarantee fee of Rs. 2 lakhs are now required to pay the remaining Rs. 3 lakhs to meet the total guarantee fee of Rs. 5 lakhs for a single course. For each additional course, the guarantee fee stands at Rs. 5 lakhs per course.

- Very important: - Please, henceforth ensure to send any compliance affidavit/reply and affiliation orders separately to complianceaffiliationcle2@gmail.com, apart from copying it to dlebcil@gmail.com. Please do not send any email/s to proledepartment@gmail.com.

For any other query/ies you may send e-mail/s to dlebcil@gmail.com

This is for your information and necessary compliance and action.

Yours sincerely,


(Nalin Raj Chaturvedi)
Joint Secretary, BCI
Additional Charge
[Legal Education Department]


(Srimanto Sen)
Secretary

PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308

Typed by: M.J
Fee & GA Checked: M.J



भारतीय विधिज्ञ परिषद् BAR COUNCIL OF INDIA

(Statutory Body Constituted under the Advocates Act, 1961)

21, Rouse Avenue Institutional Area, Near Bal Bhawan, New Delhi - 110002

BCI: D: 1211 : 2023 (LE/Std. 05.08.2023)

23.08.2023

1.	The Registrar, Chaudhary Charan Singh University, Meerut, Uttar Pradesh
2.	The Principal, Innovative Institute of Law, Plot No. 6, Knowledge Park-2, Greater Noida, Uttar Pradesh - 201308 principal640iil@gmail.com

Sub.: Extension of approval of affiliation to Innovative Institute of Law, Greater Noida, Uttar Pradesh for imparting three year LL.B course with intake of three sections of 60 students and five year BA LL.B course with intake of two sections of 60 students and fresh approval of affiliation for imparting five year B.Com LL.B course with intake of one section of 60 students for a period of one year i.e. for the academic year 2023-24.

Sir,

This is to bring to your kind knowledge that the Standing Committee of Legal Education Committee of Bar Council of India by virtue of its meeting held on 5th August, 2023 considered the matter of Innovative Institute of Law, Greater Noida, Uttar Pradesh.

After consideration, extension of approval of affiliation has been granted to Innovative Institute of Law, Greater Noida, Uttar Pradesh for imparting three year LL.B course with intake of three sections of 60 students and five year BA LL.B course with intake of two sections of 60 students and fresh approval of affiliation has also been granted for imparting five year B.Com LL.B course with intake of one section of 60 students for a period of one year i.e. for the academic year 2023-24.

Further, CLE is directed to appoint four commerce teacher, as per BCI norms through proper selection and who shall be paid UGC scale within a period of six months.

Specific conditions imposed by the inspection team and approved by the Committee which are required to be complied with are as follows:

1. There should be installed a proper sound system in bigger classrooms.
2. CLE should purchase at least one online database, such as, AIR Combo Offer, Manupatra, SCC Online, Law Finder, etc.

PRINCIPAL

Innovative Institute of Law
Plot No. 6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308

PRINCIPAL

3. CLE should transfer the Legal Aid Centre from the first floor to ground floor.
4. Ramp should be improved.

AFFIDAVIT-

---An undertaking of complying with all the conditions mentioned above must be fulfilled/submitted to BCI within 15 days of receipt of this letter.

Thereafter compliance has to be done at the earliest, within a period of 6 months from the date of receipt of this letter. A compliance affidavit (duly notarized) along with supporting documents has to be filed within the same period.

You are requested to kindly note that you will be required to seek extension of approval of affiliation for the above said course/s after approval of affiliation given by BCI ceases.

Kindly note that upon grant of approval, it shall be necessary for the Centre of Legal Education to deposit Rupees Five Lakh per course in shape of guarantee fee to fulfill all the norms of the Bar Council of India.

The same shall be liable to be forfeited if norms are not complied with and same shall carry no interest.

The letter is thus also subject to the payment of guarantee amount as mentioned effective from date of approval of affiliation.

Further details regarding payments including any Institutional Development fee etc, due, if any, shall be intimated to you in due course.

You may kindly bear in mind that the Bar Council of India is the sole and supreme sanctioning authority for seats and as a general rule it does not allow any supernumerary quota of seats for law degree courses, over and above the sanctioned strength of seats and whatever reservation of seats is to be done by the University as a general rule has to be done within sanctioned strength of seats.

A. Conditions/Rules of Legal Education regarding which compliance affidavit has to be filed.

---Further kindly ensure to furnish authenticated and signed bank statements of salary transferred to your faculty bearing bank stamp/seal and signature of the bank manager for a period of three months with effect from the date of receipt of this letter for the preceding period of three months must be furnished immediately. This must be continued to be submitted every three months without fail.

Kindly also furnish purchase receipts of Indian Bar Review and other minimum Library requirement, failing which the Centre of Legal Education shall be liable to the natural consequences, which may include revocation of recognition/approval granted.

Centre of Legal Education (CLE) as defined under the Rules of Legal Education stands for the following and is being reproduced below for convenience:

"Centres of Legal Education" means (a) All approved Departments of Law of Universities, Colleges of Law, Constituent Colleges under recognized Universities and affiliated Colleges or Schools of law of recognized Universities so approved.

Provided that a Department or College or Institution conducting

PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No-6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308

B. The Centre of Legal Education is directed to ensure compliance of the conditions stipulated above and also comply with Legal Education Rules 2008, failure of which may lead to subsequent necessary and proper action being taken in this regard :-

1. The Centre of Legal Education is directed to ensure establishment and continuance of a Legal Aid Centre as per Clause-11, Schedule-III of Rule-11 of the Part-IV of the Legal Education Rules - 2008. CLE should keep activated Legal Aid Clinic.
2. Centre of Legal Education must ensure to teach clinical subjects and give marks as per the schedule.
3. Centre of Legal Education should ensure the payment of salary to teachers as per Rules 22 schedule III, Part IV of BCI Rules.
4. The library should be furnished as per Clause 15 of Schedule III of Legal Education Rules 2008 given below :-
Minimum Library requirement: To start with, a Law Library shall have a set of AIR manual, Combo offer of CD of AIR Pvt. Ltd. (containing electronic version of AIR Supreme Court and High Court Data bases Research 1950-2015 (four connections each) Cr. L.J. Data Base 1950-2015 (four connections) AIR Privy Council Data Base 1900-1950 (four connections) AIR Manual latest 6th Edition (1-45 Vols.) AIR Journal 2015, Cr. L.J. 2015, L.I.C. 2015, AIR Civil Cases 2015, AIR Law Lines 2015, AIR Cheque Dishonour Reports 2015, AIR Accident Claims and compensation 2015, Institution shall get electronic versions updated every year by AIR Pvt. Ltd. Central Acts and Local Acts, Criminal law journal, SCC, Company cases, Indian Bar Review, selected Judgements on Professional Ethics and Journals with the back volumes for at least ten years and also such number of text books in each subjects taught during the period according to the minimum standard ratio of ten books for each registered students. For running integrated program, text books of such other subjects are also to be kept in the similar minimum ratio.
5. The Centre of Legal Education should keep in mind that minimum 10 sets of Indian Bar Review, selected judgments and professional Ethics published by Bar Council of India Trust and the AIR volumes/set must be promptly ordered for the library if not already ordered, as it is an essential requirement to run a law college which is stipulated by Bar Council of India, Legal Education Rules 2008 framed under a Parliament Act.
6. The Center of Legal Education is directed to make a minimum investment as provided below for upgrading it's library as per the following guideline :-
"Today with the increasing cost of journals, books, wi-fi, e-library and online facilities including I.T. facilities, the minimum investment by each university should be Rs. 10 lakhs for each year. However for any university/deemed university in rural area, the investment should be Rs. 5 Lakh and for all other approved colleges in the urban area it should be Rs. 2 lakhs and in rural area it should be Rs. 1 lakh."
7. Teacher Student ratio shall be 1:40 as per Schedule-III, Rule-11, Clause-17, Part-IV of Bar Council of India Rules.

PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No-6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308

PRINCIPAL

8. Centre of Legal Education is directed to inform the timings of the classes.
9. Centre of Legal Education must ensure that not less than three percent seats are reserved for persons with disabilities.
10. Centre of Legal Education shall equip itself to provide appropriate facilities in terms of the physical infrastructure, academic infrastructure and any other facilities required for the effective participation of disabled students, teachers and staff in their respective activities. For e.g. (a) ramps in public buildings and (b) Braille symbols and auditory signals in elevators or lifts.

C. Further, the Centre of Legal Education should maintain the timing which has to be minimum 5 ½ hours with half an hour break.

Rule (xxiii), Chapter I

"(xxiii) "Regular Course of Study" means and includes a course which runs for at least five hours a day continuously with an additional half an hour recess every day and running not less than thirty hours of working schedule per week."

Rule 5 of Schedule III

"Classes may be conducted between 8 a.m. to 7 p.m. in a Centre of Legal Education, which is not fully residential. However the Library may remain open till 10 p.m."

D. Further, the Centre of Legal Education should follow the attendance rule and file affidavit that they are following the aforesaid and below mentioned rule. The next inspection team shall also see whether the said rules are being followed by the university or not. The relevant Rule 12 is given below :-

"12. End Semester Test: No student of any of the degree program shall be allowed to take the end semester test in a subject if the student concerned has not attended minimum of 70% of the classes held in the subject concerned as also the moot court room exercises, tutorials and practical training conducted in the subject taken together.

Provided that if a student for any exceptional reasons fail to attend 70% of the classes held in any subject, the Dean of the University or the Principal of the Centre of Legal Education, as the case may be, may allow the student to take the test if the student concerned attended at least 65% of the classes held in the subject concerned and attended 70% of classes in all the subjects taken together. The similar power shall rest with the Vice Chancellor or Director of a National Law University, or his authorized representative in the absence of the Dean of Law.

Provided further that a list of such students allowed to take the test with reasons recorded be forwarded to the Bar Council of India."

PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida/201308

PRINCIPAL

E. Centre of Legal Education should also admit students as per the below mentioned Rule;

7. Minimum marks in qualifying examination for admission: Bar Council of India may from time to time, stipulate the minimum percentage of marks not below 45% of the total marks in case of general category applicants, 42% for OBC category and 40% of the total marks in case of SC and ST applicants, to be obtained for the qualifying examination, such as +2 Examination in case of Integrated Five Years' course or Degree course in any discipline for Three years' LL.B. course, for the purpose of applying for and getting admitted into a Law Degree Program of any recognized University in either of the streams.

Provided that such a minimum qualifying marks shall not automatically entitle a person to get admission into an institution but only shall entitle the person concerned to fulfill other institutional criteria notified by the institution concerned or by the government concerned from time to time to apply for admission.

F. Centre of Legal Education to follow Clause-24, Schedule-II of Legal Education Rule-2008 lays down Moot Court exercises and Internship; Clause-25, Schedule-III lays down Minimum period of Internship which is quoted hereunder.

(i) 24. Moot court exercise and Internship:

This paper may have three components of 30 marks each and a viva for 10 marks.

(a) Moot Court (30 Marks). Every student may be required to do at least three moot courts in a year with 10 marks for each. The moot court work will be on assigned problem and it will be evaluated for 5 marks for written submissions and 5 marks for oral advocacy.

(b) Observance of Trial in two cases, one Civil and one Criminal (30 marks):

Students may be required to attend two trials in the course of the last two or three years of LL.B. studies. They will maintain a record and enter the various steps observed during their attendance on different days in the court assignment. This scheme will carry 30 marks.

(c) Interviewing techniques and Pre-trial preparations and Internship diary (30 marks):

Each student will observe two interviewing sessions of clients at the Lawyer's Office/ Legal Aid Office and record the proceedings in a diary, which will carry 15 marks. Each student will further observe the preparation of documents and court papers by the Advocate and the procedure for the filing of the suit/petition. This will be recorded in the diary, which will carry 15 marks.

(d) The fourth component of this paper will be Viva Voce examination on all the above three aspects. This will carry 10 marks.

(ii) 25. Minimum Period of Internship: (a) Each registered student shall complete minimum of twelve weeks internship for Three Year Course stream and twenty weeks in case of Five Year Course stream during the entire period of legal studies under NGO, Trial and Appellate Advocates, Judiciary, Legal Regulatory authorities, Legislatures and Parliament, Other Legal

PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No. 6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308

Government and other such bodies as the University shall stipulate, where law is practiced either in action or in dispute resolution or in management.

Provided that internship in any year cannot be for a continuous period of more than Four Weeks and all students shall at least gone through once in the entire academic period with Trial and Appellate Advocates.

(b) Each student shall keep Internship diary in such form as may be stipulated by the University concerned and the same shall be evaluated by the Guide in Internship and also a Core Faculty member of the staff each time. The total mark shall be assessed in the Final Semester of the course in the 4th Clinical course as stipulated under the Rules in Schedule II.

G. Centre of Legal Education should also follow Rule- 10 of Legal Education Rules 2008 which is quoted hereunder :-

10. Semester system

The course leading to either degree in law, unitary or on integrated double degree, shall be conducted in semester system in not less than 15 weeks for unitary degree course or not less than 18 weeks in double degree integrated course with not less than 30 class-hours per week including tutorials, moot court room exercise and seminars provided there shall be at least 24 lecture hours per week.

Provided further that in case of specialized and/or honours law courses there shall be not less than 36 class-hours per week including seminar, moot court and tutorial classes and 30 minimum lecture hours per week.

Provided further that Universities are free to adopt trimester system with appropriate division of courses per trimester with each of the trimester not less than 12 weeks.

H. Centre of Legal Education should also follow Rule 17 and Rule 18 of Schedule III of Legal Education Rules 2008 which is quoted hereunder :-

(i) **Rule 17. Core Faculty:**

There shall be sufficient number of full time faculty members in each Centre of Legal Education (i.e. Department, constituent or affiliated college) to teach each subject at all point of time for running courses who can be supported by part time or visiting faculty. Such a core faculty shall in no case be less than six in the first year of the approval with both streams in operation, eight in the second year and ten in the case of third year of law courses. In addition, for the integrated course qualification as is required under the UGC guideline or under such other standard setting body as the discipline is allotted to by any Act, statute, or Rules of the Government of India or of a State.

For the Three Year Bachelor of Law degree course only with two sections without the Honour program, there shall be minimum of 4 core faculty in the first year six in the second and eight in the third year in addition to the Principal/ Head or Dean as the case may be.

Provided that an institution intending to run any specialized or honours course must have at least three faculty in the group in which specialization and honours courses are offered.

Provided further that each full time faculty shall take as many classes in the subject or subjects as may be assigned to them on the basis of standard prescribed by 'the standard setting institution' like UGC.

PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No. 6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308

Provided further, if any institution of a University, which was already affiliated to the University and approved to run professional courses of either scheme or both by the Bar Council of India after inspection of the University, falls short of required full time faculty, the new admission in courses may be required to remain suspended until new required number of faculty is procured. The University shall before starting a new academic session, notify which institutions are only be allowed to admit fresh students.

Provided further that if while inspecting the University it was found that in any institution of the University adequate number of full time faculty was not there in the staff, the Bar Council after giving notice to the University might give a public notice directing the University not to admit students in the new academic year in that institution.

There shall be adequate faculty in the subjects offered in the liberal educational subjects as part of the course by the institution. These faculties in the liberal educational discipline in Arts, Science, Management, Commerce, Engineering, Technology or any other discipline shall possess

(ii) **Rule -18 Minimum weekly class program per subject (paper):.**

There shall be for each paper (with 4 credit) Four class-hours for one hour duration each and one hour of tutorial/moot court/project work per week.

AFFIDAVIT-


Kindly ensure to comply with all the above stipulated and all other requisite Rules of Legal Education 2008 by way of duly notarized compliance affidavit by attaching adequate documentation proof with the same with a period of 6 months for being eligible to be issued further Approval for further subsequent academic years and failure to furnish the same shall make the CLE liable to the natural consequences which may include revocation of recognition/approval granted.


This letter is subject to final approval/confirmation of the Legal Education Committee and General Council of the Bar Council of India.

You are also requested to attach a copy of this letter with your compliance report/reply.

It is suggested that all information should be provided to Bar Council of India both in hard and soft copy/pen-drive and by email at complianceaffiliationlc2@gmail.com.

This is for your information and necessary action.


(Mallin Raj Chaturvedi)
Joint Secretary, BCI
(Legal Education Department)


(Ashok Kumar Pandey)
Joint Secretary
HOD, Legal Education Dept.

Yours sincerely,

PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308


(Srimanto Sen)
Secretary

Email: bcinfo21@gmail.com
info@barcouncilofindia.org
Website: www.barcouncilofindia.org



Tel: (91) 011-4922 5000
Fax: (91) 011-4922 5011

भारतीय विधिज्ञ परिषद् BAR COUNCIL OF INDIA

(Statutory Body Constituted under the Advocates Act, 1961)

21, Rouse Avenue Institutional Area, Near Bal Bhawan, New Delhi - 110002

BCI: D:५७) /2022 (LE/App/Afflin)

Dated 03.08.2022

To,

1	The Registrar, Chaudhary Charan Singh University Meerut - 250001 Uttar Pradesh
2	The Principal, Innovative Institute of Law, Plot No. 6, Knowledge - 2, Greater Noida - 201308 Uttar Pradesh

Sub: Extension of provisional temporary approval of affiliation to Innovative Institute of Law, Greater Noida, Uttar Pradesh for three year LL.B as well as five year BA LL.B law courses for the academic year 2022-2023 with the prevalent/existing sections (earlier specifically approved in writing by BCI) with intake of not more than 60 students in one section.

Sir,

This is with reference to above mentioned subject regarding extension of provisional approval of affiliation Innovative Institute of Law, Greater Noida, Uttar Pradesh which has already applied for extension of approval of affiliation for the academic year 2022-2023

This is to bring to your kind knowledge that the following resolution was passed on 08th June, 2022 by the General Council of the Bar Council of India with respect to grant of provisional approval of affiliation for academic year 2022-2023 for those centers of Legal Education which have applied for approval of affiliation for the academic year 2022-2023.

"RESOLVED that with respect to existing Centers of Legal Education/colleges, whose inspection fee has been deposited, application for extension of approval of affiliation is pending, no inspection could be done or the inspection has been done, but inspection report could not be placed before the Legal Education Committee of the

Typed by
Fee & GA Checked M
Default Amt. JCT
Compliance JCT
Meeting letter M

SECRETARY
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida - 201308

PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308

Standing Committee for its consideration, such Centers of Legal Education/colleges may continue to admit students only for the academic year 2022-2023. This will apply only in case where affiliation has been granted by the University, Such provisional approval shall be subject to any decision taken after the inspection of the CLE is done by the Bar Council of India subsequently.

It shall further be conditional and is subject to compliance as per circular dated 05.02.2020 bearing No.BCI:D:158 (LE:Circulation No.01/2020), issued to all Centers of Legal education, as per the extended time of such compliance which shall be 31st August, 2022, whereby every center of Legal Education/college shall be required to submit a certified authenticated bank statement bearing bank stamp, date and signature, mandatorily with respect to the salary/ies being disbursed to all the teachers/faculties every three months with effect from March, 2022 on a regular basis, unless specifically sought at other intervals, and also furnish list of teachers with qualifications as per BCI and UGC Rules, and further furnish proof/receipts of fulfilment of minimum library requirements, as emanated under Schedule-III, Rule-15, Minimum Library requirements of Legal Education Rules-which is the sine qua non of a Center of Legal Education. Certain show cause notices and compliance letters had also been issued specifically to certain Centers of Legal Education/Colleges, with conditions mentioned therein, which have to be complied too as per the time stipulations therein, and if they have not been complied with they must be complied with immediately or latest by 31st August, 2022.

However, regardless of the date of 31st August, 2022 for compliance, an affidavit undertaking to comply with the conditions mentioned in the above referred circular and of all the rules of Legal Education, shall be required to be submitted by way of duly notarized affidavit within 15 days of receipt of this letter by way of hardcopy and also by way of scanned copy at complianceaffiliationie2@gmail.com with heading-COMPLIANCE TO PROVISIONAL APPROVAL-REQUIREMENTS

It is made clear that if any Center of Legal Education, fails to submit all the required documents as sought by way of the afore referred circular and the show cause notices (where applicable), and the compliance letters, already issued, by 31st August, 2022, then their application for extension of approval for 2022-2023 shall not be considered and, if, approval is granted for the academic session 2022-2023, it may be withdrawn too.

SECRETARY

Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida 201306

B. Shamma

Typed by
Fee & GA checked MJ
Default Anst JCT
Compliance JCT
Meeting Letter MJ

A
J. Prasad
A
J. Prasad

PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308

You may kindly bear in mind that the Bar Council of India is the sole and supreme sanctioning authority for seats and as a general rule it does not allow any supernumerary quota of seats for law degree courses, over and above the sanctioned strength of seats and whatever reservation of seats is to done by the University as a general rule has to be done within sanctioned strength of seats.

The Center/s of Legal Education/College may take a note of the above mentioned facts and furnish compliance of the same and of the other rules and regulations of Legal Education, including the stipulations specified in the abovesaid referred circular/s, show cause notices and compliance letters, and in ANNEXURE-A, attached to this provisional approval of affiliation letter, which is required be complied with adequate documentary proof and by way of a notarized affidavit, by 31st August, 2022 failing which as stated above their application for extension of approval for 2022-23 shall not be considered and if approval, is granted for the academic session 2021-2022, the same may be withdrawn too."

Since your University has given affiliation for the academic year 2022-2023, you are requested to allow Innovative Institute of Law, Greater Noida, Uttar Pradesh to admit students in three year LL.B as well as five year BA LL.B law courses with the prevalent/ existing (earlier approved by BCI) sections, for the academic year 2022-2023

This is for your information and necessary action.

[Nalin Raj Chaturvedi]
Asstt. Secretary
Bar Council of India
Legal Education Department

[Ashok Kumar Pandey]
Joint Secretary
(H.O.D)
Legal Education Department

Typed by
Fee & GA Checked MJ
Default Amt. ICT
Compliance ICT
Meeting Letter MJ

[Handwritten initials]

SECRETARY
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida 201308

[Srimanto Sen]
Secretary
Bar Council of India

SECRETARY
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida 201308

PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308

Note – Kindly ensure to submit English translation of all documents being furnished by you in Hindi or in any other regional language to BCI.

Note – Your University is requested to kindly verify the authenticity of the attached affiliation order submitted by the Centre of Legal Education and revert back to the Bar Council of India through e-mail as soon as possible.

Note – The refundable guarantee amount (basic amount) is Rs. 5 lacs and if the guarantee amount is not paid immediately after initial grant of approval, you are liable to be levied with an interest or penalty for late deposit of Guarantee Amount.

Very important: - Please, henceforth ensure to send any compliance affidavit/reply and affiliation orders separately to complianceaffiliationle2@gmail.com, apart from copying it to dlebci@gmail.com please do not send any email/s to proledepartment@gmail.com.

For any other query/ies you may send e-mail/s to dlebci@gmail.com

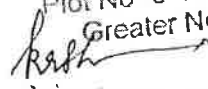
Copy to

The Secretary
Bar Council of Uttar Pradesh
19, Maharishi Dayanand Marg,
Allahabad, Uttar Pradesh


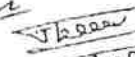
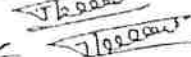



PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308

SECRETARY
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida 201306



SECRETARY
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida 201306

Typed by
Fee & GA Checked AU 
Default Amt. JCT 
Compliance JC 
Meeting Letter Mj 

E-mail : info@barcouncilofindia.org
Website : www.barcouncilofindia.org



Tel. : (91) 011-4922 50
Fax : (91) 011-4922 50

भारतीय विधिज्ञ परिषद् BAR COUNCIL OF INDIA

(Statutory Body Constituted under the Advocates Act, 1961)

21, Rouse Avenue Institutional Area, Near Bal Bhawan, New Delhi - 110002

BCI: D: 558 /2021 (LE/App/Affin)
To,

Dated 28.06.2021

The Registrar,
Chaudhary Charan Singh University
Meerut, - 250001
Uttar Pradesh

Sub: Extension of provisional temporary approval of affiliation to Innovative Institute of Law, Greater Noida, Uttar Pradesh for three year LL.B as well as five year BA LL.B law courses for the academic year 2021-2022 with the prevalent/existing sections (earlier specifically approved in writing by BCI) with intake of not more than 60 students in one section.

Sir,

This is with reference to above mentioned subject regarding extension of provisional approval of affiliation Innovative Institute of Law, Greater Noida, Uttar Pradesh which has already applied for extension of approval of affiliation for the academic year 2021-2022.

This is to bring to your kind knowledge that the following resolution was passed on 24th June, 2021 by the standing committee of Legal Education Committee of Bar Council of India: with respect to grant of provisional approval of affiliation for academic year 2021-2022 for those centers of Legal Education which have applied for approval of affiliation for the academic year 2021-2022.

RESOLVED that the existing Centers of Legal Education inclusive of Recognized Universities, University Law Departments, colleges/Law Schools (i) whose inspection fee has been deposited and application for extension of approval of affiliation is pending, but, no inspection could be done; or (ii) though the inspection has been done, but inspection report could not be placed before the Legal Education Committee or before the Standing Committee for its consideration, such Centers of Legal Education/colleges are allowed to continue to admit students. However, this approval is accorded only for the academic year 2021-2022. It is further made clear that this will apply only in case where affiliation has been granted by the University. Such provisional approval by Bar Council of India shall be subject to any decision taken after the inspection of the Centre of Legal Education.

Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida 201306

SECRETARY
Institute of Law
Knowledge Park-2
Greater Noida, 201306
[Signature]
PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308

As per the circular dated 05.02.2020 bearing No.BCI:D:158 (LE:Circulation No.01/2020), issued to all Centers of Legal education, and as per the extended time for such compliance (The Council has extended the time for such compliance to 15th August, 2021), every center of Legal Education/college shall be required to submit a certified authenticated bank statement bearing bank stamp, date and signature, mandatorily with respect to the salary/ies being disbursed to all the teachers/faculties every three months from date of receipt of communication on a regular basis, unless specifically sought at other intervals.

The Centers of Legal Education shall also furnish list of teachers with qualifications as per BCI and UGC Rules, and further furnish proof/receipts of fulfillment of minimum library requirements, as enumerated under Schedule-III, Rule-15, Minimum Library requirements of Legal Education Rules-which is the sine qua non of a Center of Legal Education. Show cause notices had also been issued specifically to certain Centers of Legal Education/Colleges, with conditions mentioned therein to be complied with immediately.

It is made clear that if any Center of Legal Education, fails to submit all the required documents as sought by way of the referred circular and the show cause notices (where applicable), within the stipulated/extended time for such compliance, then application for extension of approval for 2022-2023 of such Centers of Legal Education shall not be considered and, if, approval is granted for the academic session 2021-2022 by way of any reason whatsoever, then it may be withdrawn too.

The Centers of Legal Education/College may take a note of the above mentioned facts and furnish compliance of the same and of the other rules and regulations of Legal Education, including the stipulations specified in ANNEXURE-A, attached to this provisional approval of affiliation letter. This is required to be complied with by/on/before 15.08.2021 with adequate documentary proof(s) and by way of a notarized affidavit. In case of failure of compliance by any Centers of Legal Education their application for extension of approval for 2022-23 shall not be considered and if approval is granted for the academic session 2021-2022, the same may be liable to be withdrawn too.

Since your university has given affiliation for the academic year 2021-2022, to this particular Centre of Legal Education you are requested to allow Innovative Institute of Law, Greater Noida, Uttar Pradesh to admit students in three year LL.B as well as five year BA LL.B law courses with the prevalent/ existing (affiler specifically approved in writing by BCI) sections for the academic year 2021-2022.

The Centre of Legal Education is requested to ensure to send to BCI, the last sanctioned written approval accorded by BCI to it, with section strength, at the earliest for verification.

This is for your information and necessary action.

Note - Kindly ensure to submit English translation of all documents being furnished by you in Hindi or in any other regional language to BCI.

PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308

SECRETARY
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida 201306

[Signature]
SECRETARY
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida 201306

Note – The refundable guarantee amount (basic amount) is Rs. 5 lacs and if the guarantee amount is not paid immediately after initial grant of approval, you are liable to be levied with an interest or penalty for late deposit of Guarantee Amount.

Very important: - Please, henceforth ensure to send any compliance affidavit/reply and affiliation orders separately to complianceaffiliationle2@gmail.com, apart from copying it to dlebc@gmail.com please do not send any email/s to prfedepartment@gmail.com.

For any other query/ies you may send e-mail/s to dlebc@gmail.com

Yours sincerely

[Ashok Kumar Pandey]
Joint Secretary
(H.O.D)
Legal Education Department

[Srimanto Sen]
Secretary
Bar Council of India

Copy to:

1. The Principal,
Innovative Institute of Law,
Plot No. 6, Knowledge - 2,
Greater Noida - 201308
Uttar Pradesh
2. The Secretary
Bar Council of Uttar Pradesh
19 Maharishi Dayanand Marg
Allahabad, Uttar Pradesh

SECRETARY
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida 201306

PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308

SECRETARY
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida 201306

E-mail info@barcouncilofindia.org
Website www.barcouncilofindia.org



Tel. (91) 011 4922 5000
Fax (91) 011 4922 5011

भारतीय विधिज्ञ परिषद्
BAR COUNCIL OF INDIA

(Statutory Body Constituted under the Advocates Act, 1961)

21, Rouse Avenue Institutional Area, Near Bal Bhawan, New Delhi - 110002

BCI: D:313 /2020 (LE/App/Affin)

Dated 22.07.2020

To,

The Registrar,
Chaudhary Charan Singh University
Meerut, - 250001
Uttar Pradesh

Sub: Provisional temporary approval of affiliation to Innovative Institute of Law, Plot No. 6, Knowledge Park - 2, Greater Noida Uttar Pradesh for three year LL.B as well as five year BA LL.B law courses for the academic year 2020-2021.

Sir,

This is with reference to above mentioned subject regarding extension provisional approval of affiliation Innovative Institute of Law, Plot No. 6, Knowledge Park - 2, Greater Noida, Uttar Pradesh which has already applied for extension of approval of affiliation for the academic year 2020-21 and inspection of the Bar council of India is pending.

The matter relating to colleges similarly placed were considered by the Standing Committee Meeting Bar Council of India at its meeting held on 24th June 2020 and passed the resolution on the same. The resolution passed was as follows:

"RESOLVED that colleges whose inspection fee has been deposited, application for extension of approval of affiliation is pending, no inspection could be done or the inspection has been done, but inspection report could not be placed before the Legal Education Committee or the Standing Committee for its consideration, then such colleges may continue to admit students only for the academic year 2020-2021. This will apply only in case where affiliation has been granted by the University which of course shall be subject to the inspection to be made by the Bar Council of India subsequently.

Committee further resolved that every law college shall be required to submit a certified bank statement mandatorily for the salary/ies being disbursed to all the teachers every three months from date of receipt of communication, which was earlier directed to comply with the above said conditions along with other conditions on or before 31st March, 2020 is now being extended till 31st October, 2020. It is made clear that if Law Colleges/Center of Legal Education fails to submit the required documents on or before 31st October, 2020 then their application for extension of approval for 2021-22 shall not be considered and/or approval already granted may be withdrawn"

PRINCIPAL

Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308

SECRETARY
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida 201306

Sham

Kash

SECRETARY

Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida 201306

The college had applied in December, 2019 for further extension of approval of affiliation for three year LLB course and five year BA.LLB course from the year 2020-21. The inspection of the college was pending, so as per the resolution of the Council, the college was granted approval for the years 2019-20. Then the college was inspected in the year 2017 and the inspection was considered by the Standing Committee and approved three year LLB course with intake of three sections of 60 students and five year BA.LLB with intake of two sections of 60 students in each section till the year 2019-2020.

Since your university has given affiliation for the year 2020-2021, you are requested to allow Innovative Institute of Law, Plot No. 6, Knowledge Park - 2, Greater Noida, Uttar Pradesh to admit students in three year LLB & five year BALLB courses with existing sections for the academic year 2020-2021.

As per the inspection report, the college is allowed to admit students for the academic year 2020-21 subject to payment of prescribed fee to the Bar Council of India. After depositing the fee the institution will be inspected by the Bar Council of India.

This is for your information and necessary action.

Very important:

Further the college will submit a list of faculties and duly certified bank statement showing transfer of salary to all the faculties as per UGC Rules before 31st March, 2020 along with duly notarized affidavit as specified in Annexure-A.

Furthermore Schedule III, Rule 15, Minimum Library requirements of Legal Education Rules-2008 is to be complied with too as specified in the said Annexure A.

Further more the requested inspection cum application / approval fee along with affiliation order of the concerned University for the year 2020-21 is to be submitted to the Bar Council of India on or before 31st March, 2020.

It is made clear that, in case, the above direction is not complied with by the college, it would not be entitled to admit any students for the next academic session beginning in July, 2020-21 and its application for extension of approval of affiliation for the session 2020-2021 will not be entertained and considered. The concerned University also should not allot any student to the college without approval of affiliation by the Bar Council of India for the academic year 2020-21 without complying the above said.

This is for your information and necessary action.

Note - Kindly ensure to submit English translation of all documents being furnished in Hindi or in any other regional language.

Note - Your University is requested to kindly verify the authenticity of the attached affiliation order submitted by the college and revert back to the Bar Council of India through e-mail as soon as possible.

Note - (1) That w.c.f 21.05.2016 the inspection fee for LL.B three year and five year regular course is Rs. 3 lacs for each course and for the

PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida - 201306

SECRETARY
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida 201306

SECRETARY
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida - 201306

Honours course it is Rs. 5 lacs, while the application fee is Rs. 50,000/- and the guarantee amount is Rs. 5 lacs.

Very important : - Please, henceforth ensure to send any compliance affidavit/ reply and affiliation orders separately to complianceaffiliationle@gmail.com, apart from copying it to dlebcil@gmail.com please do not send any email/s to proledpartment@gmail.com

For any other query/ies you may send e-mail/s to dlebcil@gmail.com

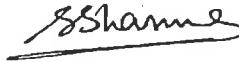
Yours sincerely



[Ashok Kr. Pandey]
Joint- Secretary

Copy to:

1. The Principal,
Innovative Institute of Law,
Plot No. 6, Knowledge Park - 2,
Greater Noida - 201308 Uttar Pradesh.
2. The Secretary
Bar Council of Uttar Pradesh
19 Maharishi Dayanand Marg
Allahabad, Uttar Pradesh



SECRETARY
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida 201308

PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308

SECRETARY
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida 201308



भारतीय विधिज्ञ परिषद्
BAR COUNCIL OF INDIA

(Statutory Body Constituted under the Advocates Act, 1961)

श्रीमंतो सेन
सचिव

SRIMANTO SEN
Secretary

21, राउज ऐवन्यू इन्सटीटूशनल एरिया
नई दिल्ली - 110 002

21, Rouse Avenue Institutional Area
New Delhi - 110 002

BCI: D: 1910 /2017 (LE/Sub-Comm. 12.11.2017)

28.11.2017

The Registrar,
Chaudhary Charan Singh University,
Meerut,
Uttar Pradesh

Letter of Consent

Sub: Extension of approval of affiliation to Innovative Institute of Law, Greater Noida, Uttar Pradesh for imparting three year LL.B course with existing strength of two sections of 60 students along with one additional section i.e. total three sections of 60 students in each section and five year BA LL.B course with existing strength of one section of 60 students along with one additional section i.e. total two sections of 60 students in each section for a period of three years i.e. for the academic years 2017-2018, 2018-2019 and 2019-2020.

Sir,

The Sub-Committee of the Legal Education Committee of the Bar Council of India considered the inspection report submitted by the inspection team of the Bar Council of India. After consideration, the Committee is of the view that the recommendation of the inspection committee be accepted.

The college was having two sections in three year LLB course and one section in five year BA.LLB course. The record discloses that apart seeking approval of affiliation of existing courses, the college requested for sanction of one more section in each course. The inspection team was also satisfied with the infrastructure and teaching staff, hence approval is accorded for three sections in three year LL.B degree course and two sections for five year BA.LLB course.

In view of the above, **Innovative Institute of Law, Greater Noida, Uttar Pradesh** be granted **extension of approval of affiliation** for imparting **three year LL.B course** with existing strength of two sections of 60 students along with one additional section i.e. **total three sections of 60 students** in each section and **five year BA LL.B course** with existing strength of one section of 60 students along with one additional section i.e. **total two sections of 60 students** in each section for a period of **three years** i.e. for the academic years **2017-2018, 2018-2019 and 2019-2020.**

Since, the College had applied in time, therefore, approval of affiliation for the earlier period i.e. from the academic year 2011-2012 to 2016-2017 is also regularized.

PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308

The University/College is directed to also fulfill the following conditions, failure of which may lead to subsequent necessary and proper action being taken in this regard.

1. The Institution is directed to establish the Legal Aid Centre as per Clause-11, Schedule-III of Rule-11 of the Part-IV of the Legal Education Rules - 2008.
2. Institution should ensure the payment of salary to teachers as per Rules 22 schedule III, Part IV of BCI Rules.
3. The library should be furnished as per Clause 15 of Schedule III of Legal Education Rules 2008 is given below :-

Minimum Library requirement: To start with, a Law Library shall have a set of AIR manual, Combo offer of CD of AIR Pvt. Ltd. (containing electronic version of AIR Supreme Court and High Court Data bases Research 1950-2015 (four connections each) Cr. L.J. Data Base 1900-1950 (four connections) AIR Privy Council Data Base Edition(1-45 Vols.) AIR Journal 2015, Cr. L.J. 2015, L.I.C. 2015, AIR Civil Cases 2015, AIR Law Lines 2015, AIR Cheque Dishonour Reports 2015, AIR Accident Claims and compensation 2015, Institution shall get electronic versions updated every year by AIR Pvt. Ltd. Central Acts and Local Acts, Criminal law journal, SCC, Company cases, Indian Bar Review, selected Judgements on Professional Ethics and Journals with the back volumes for at least ten years and also such number of text books in each subjects taught during the period according to the minimum standard ratio of ten books for each registered students. For running integrated program, text books of such other subjects are also to be kept in the similar minimum ratio.

4. The institution should keep in mind that minimum 10 sets of Indian Bar Review, selected judgments and professional Ethics published by Bar Council of India Trust and the AIR volumes/set must be promptly ordered for the library if not already ordered.
5. The institution is directed to upgrade the library as mentioned below :-

"Today with the increasing cost of journals, books, wi-fi, e-library and online facilities including I.T. facilities, the minimum investment by each university should be Rs. 10 lakhs for each year. However for any university/deemed university in rural area, the investment should be Rs. 5 Lakh and for all other affiliated colleges in the urban area it should be Rs. 2 lakhs and in rural area it should be Rs. 1 lakh."

6. Teacher Student ratio shall be as per Schedule-III, Rule-11, Clause-17, Part-IV of Bar Council of India Rules.
7. Institution is directed to inform the timings of the classes.
8. College Management should establish a computer lab for the development of Law students.

PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308

9. A Centre of Legal Education must ensure that not less than three percent seats are reserved for persons with disabilities.
10. Centre of Legal Education shall equip itself to provide appropriate facilities in terms of the physical infrastructure; academic infrastructure and any other facilities required for the effective participation of disabled students, teachers and staff in their respective activities. For e.g. (a) ramps in public buildings and (b) Braille symbols and auditory signals in elevators or lifts.

Further, the University/College must specify the timing of the college which has not been given. College should also maintain the timing which has to be minimum 5 ½ hours with half an hour break. **College is directed to file an affidavit to the Bar Council of India within six weeks mentioning the timing of the classes.** The relevant rules are quoted hereunder :-

Rule (xxiii), Chapter I

“(xxiii) “Regular Course of Study” means and includes a course which runs for at least five hours a day continuously with an additional half an hour recess every day and running not less than thirty hours of working schedule per week.”

Rule 5 of Schedule III

“Classes may be conducted between 8 a.m. to 7 p.m. in a Centre of Legal Education, which is not fully residential. However the Library may remain open till 10 p.m.”

Further, the institution should follow the attendance rule and file reply that they are following the aforesaid rule. The next inspection team must also see whether the said rule is being followed by the university or not. The relevant Rule 12 is given below :-

“12. End Semester Test: No student of any of the degree program shall be allowed to take the end semester test in a subject if the student concerned has not attended minimum of 70% of the classes held in the subject concerned as also the moot court room exercises, tutorials and practical training conducted in the subject taken together.

Provided that if a student for any exceptional reasons fail to attend 70% of the classes held in any subject, the Dean of the University or the Principal of the Centre of Legal Education, as the case may be, may allow the student to take the test if the student concerned attended at least 65% of the classes held in the subject concerned and attended 70% of classes in all the subjects taken together. The similar power shall rest with the Vice Chancellor or Director of a National Law University, or his authorized representative in the absence of the Dean of Law.

Provided further that a list of such students allowed to take the test with reasons recorded be forwarded to the Bar Council of India.”

University/College should also admit students as per the below mentioned Rule:

PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308

7. Minimum marks in qualifying examination for admission: Bar Council of India may from time to time, stipulate the minimum percentage of marks not below 45% of the total marks in case of general category applicants, 42% for OBC category and 40% of the total marks in case of SC and ST applicants, to be obtained for the qualifying examination, such as +2 Examination in case of Integrated Five Years' course or Degree course in any discipline for Three years' LL.B. course, for the purpose of applying for and getting admitted into a Law Degree Program of any recognized University in either of the streams.

Provided that such a minimum qualifying marks shall not automatically entitle a person to get admission into an institution but only shall entitle the person concerned to fulfill other institutional criteria notified by the institution concerned or by the government concerned from time to time to apply for admission.


Institution should submit affidavit in compliance of the above conditions within six weeks.


The University/College authorities are also required to apply before the Bar Council of India for further extension of approval six months in advance before expiry of the period of approval of affiliation being presently granted by the Bar Council of India. i.e. on or before 31st December, 2019.

This letter is subject to final approval/confirmation of the Legal Education Committee and General Council of the Bar Council of India.

This is for your information and necessary action.

Yours Sincerely,


(Srimanto Sen)
Secretary


Copy to:-

1. The Principal,
Innovative Institute of Law,
Plot No. 6, Knowledge Park-2,
Greater Noida,
Uttar Pradesh
Innovative_college@rediffmail.com

PRINCIPAL
Innovative Institute of Law
Plot No -6 Knowledge Park-2
Greater Noida-201308